International Journal of Hindi Research
www.hindijournal.com
ISSN: 2455-2232
Received: 27-10-2025, Accepted: 26-11-2025, Published: 11-12-2025
Volume 11, Issue 4, 2025, Page No. 134-137

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्थायी विकास के 'गुणवत्ता शिक्षा' लक्ष्य को पूरा करेगी?

डॉ. प्रबोधिनी बा. वाखारे[1], भाग्यश्री बोर्‌हाडे[2], डॉ. शिवाजी बोर्‌हाडे[3]

[1] असिस्टेंट प्रोफेसर, भारतीय जैन संघटना कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, वाघोली, पुणे, महाराष्ट्र, भारत
[2] रिसर्च स्कॉलर, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे, प्रा. रामकृष्ण मोर कॉलेज, आकुर्डी, पुणे, महाराष्ट्र, भारत
[3] प्रोफेसर एवं प्रधानाचार्य, पद्मश्री मणिभाई देसाई महाविद्यालय, ऊरुळी कांचन, पुणे, महाराष्ट्र, भारत

सारांश

भारतीय शिक्षा पद्धति में मौलिक सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने २०२० में नई राष्ट्रीय शैक्षिक नीति का स्वीकार किया है। शिक्षा का सामान्यीकरण करके भारत को विश्व में ज्ञान की महाशक्ति बनाने के उद्देश्य से बनाई गयी इस नीति का संयुक्त राष्ट्र के स्थायी विकास के उद्देश्यों के साथ मेल करना बेहद आवश्यक है। २०३० तक विश्व ने स्थायी विकास के लक्ष्यों को पूरा करने का निर्धारित किया है। स्थायी विकास के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत ने भी उसी दिशा में अपनी नीति को स्थापित किया है। स्थायी विकास का चौथा लक्ष्य गुणवत्ता शिक्षा है। भारत इस शैक्षिक नीति के माध्यम से उसे साकार कर सकता है या नही यह देखना इस अभ्यास का विषय है। भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक नेतृत्व के लिए उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षा की आवश्यकता है, और यह अभ्यास इस निष्कर्ष को प्राप्त करने में सहायक होगा। इस संशोधन का निष्कर्ष है कि गुणवत्ता शिक्षा को वैश्विक उद्देश्यों को साकार करने के लिए भारत की शिक्षा नीति के साथ मेल तो होता है, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश जब तक जीडीपी के ६ फिसदी तक पहुंचता नही तब तक स्थायी विकास का लक्ष्य पुरा करना मुश्किल माना जाता है।

मूल शब्दः राष्ट्रीय शैक्षिक नीति, स्थायी विकास, वैश्विक उद्देश्य, गुणवत्ता शिक्षा, स्थायी विश्व

कोई भी देश अपने समग्र विकास के लिए लगातार प्रयासशील होता है। आर्थिक महत्त्व हासिल करने के लिए या विकसित बनने के लिए विश्वभर के देशो ने मान्य धारणाओं को अपनाया है, जिससे पर्यावरण और प्राकृतिक संपत्ति के महत्वपूर्ण घटकों का प्रमाण तेजी से कम हो रहा है। वही पर, स्थायी विकास की दिशा में एक नई सोच विकसित हो रही है। 'स्थायी विकास' का मतलब है केवल वर्तमान स्थिति को देखना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए योजनाबद्ध प्रयास और दूसरों के सुरक्षित भविष्य के लिए योजनाबद्ध प्रयास करना। पर्यावरण विषयक, आर्थिक और सामाजिक मांग को संतुलित करने के लिए स्थायी विकास की आवश्यकता है! क्योंकि यह विकास संसाधानों के न्यायिक और इस्तेमाल के समान दायित्व के साथ होने की गारंटी देकर उनकी मेहनत को भरपूर बनाता है।

स्थायी विकास के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और सांगठनिक– ये सभी एक विशिष्ट चार पहलु हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक उद्देश्यों को निश्चित किया है जिसे 'स्थायी विकास', 'स्थितिगत विकास' या 'निरंतर विकास' के रूप में भी पहचाना जाता है। इनमें से सभी 17 उद्देश्य शामिल हैं, जिनमें शिक्षा, गरीबी, सुरक्षा, जल, वायु परिवर्तन, पर्यावरण, स्वच्छता, पानी, ऊर्जा, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय आदि शामिल हैं। 'गुणवत्ता शिक्षा' यह स्थायी विकास का चौथा उद्देश्य है, जिसमें सभी के लिए न्यायमूलक और समान शिक्षा सुनिश्चित करने और दुनिया भर में पढ़ाई के अवसरों को प्रोत्साहित करने की आशा है।

'गुणवत्ता शिक्षा' स्थायी विकास के चौथे उद्देश्य के रूप में भारत को यहां तक कि उसे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सभी के लिए शिक्षा को सुनिश्चित किया जाए और विश्वभर में शिक्षा के अवसरों को प्रोत्साहित किया जाए। अधिक बेहतर स्थायी जगह की प्राप्ति के लिए बेहतर शिक्षा एक आवश्यक साधन है। स्थायी विकास के लिए शिक्षा जिनके लिए अगर पर्यावरण की रक्षा और जतन की जिम्मेदारी है, सामाजिक समानता को बढ़ावा देती है, और आर्थिक स्थायीता को प्रोत्साहित करती है। भारत ने स्थायी विकास की दृष्टि से पहले कदम रखा है, और इसकी जिम्मेदारी नीति आयोग को सौंपी गई है। इस स्थायी विकास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान, मनरेगा, आधार कायदा, सागरमाला जैसी कई प्रकार की योजनाएँ शुरू की है। इसके साथ नई शिक्षा नीति २०२० लागू करने की दिशा में भी सरकार की पहल शुरू हो चुकी है।

अध्ययन का उद्देश्य

भारतीय शिक्षा नीति तथा स्थायी विकास के संदर्भ मे प्रचुर मात्रा मे साहित्य उपलब्ध है किंतु नई शिक्षा नीति और स्थायी विकास के दिशा में अधिक प्रयास नही किये गये। अतः इस दृष्टिकोण को सम्मुख रख प्रस्तुत शोध में अध्ययन के लिए निम्न लिखित उद्देश्य उद्देश निरुपित किये गये है।

1. स्थायी विकास की दिशा में गुणवत्ता शिक्षा के आवश्यक घटकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल किया गया है यह तलाशना।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० स्थायी विकास की दिशा के अनुकूल है क्या इसका अध्ययन करना।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति और स्थायी विकास की गुणवत्ता शिक्षा का उद्देश्य पूरा होने का संबंध में दृष्टिकोण जांचना।

परिकल्पना

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति और स्थायी विकास की गुणवत्ता शिक्षा के लक्ष्य का पूरा होना इसमें कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति और स्थायी विकास की गुणवत्ता शिक्षा के लक्ष्य का पूरा होना इसमें महत्वपूर्ण संबंध है।

साहित्य सर्वेक्षण

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर काफी कम संशोधन किया गया है। लोगों को इस नीति की कल्पना के बारे में अवगत करने के लिए सरकार ने कुछ प्रयास जरूर किए हैं। यह नई नीति कई तरह की विशेषताओं के साथ है, खासकर छात्रोंकेंद्रित और उनकी क्षमता के आधार पर स्थायी मूल्यांकन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, प्रवेश

प्रक्रिया, संशोधन, विषय चयन, और स्वतंत्रता जैसी विभिन्न विशेषताओं के साथ है। भारतीय शिक्षा नीति तथा स्थायी विकास के संदर्भ मे जो साहित्य उपलब्ध है उसका अवलोकन आगे किया गया है।

नागपाल (२०२३) ने शाला शिक्षा के चुनौतियों का अध्ययन किया है और इस शिक्षा नीति के प्रभावी अंमलबजावणी के लिए सततता और सभी की भागीदारी की मांग की है। इस मानक ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में परिवर्तन को प्रोत्साहित किया है और देश के समग्र विकास को पूरा करने का दावा किया है। चव्हाण (२०२३) के अनुसार, सरकारने कोविड के समय गंभीर स्थितियों के बावजूद इस शिक्षा नीति को तेजी से लागू किया है। हालांकि इसे बेहद उपयुक्त बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन इसमें आवश्यक और सुधार किया जा सकता है।

अभय कुमार (२०२२) ने अपने अध्ययन में एक नई शैक्षिक धारा के बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के बारे में चर्चा की है। इस नई धारा के तहत, उन्होंने बलस्थान और कमकुवत स्थानों के लिए गुणवत्ता पूर्ण विद्यापीठों और महाविद्यालयों की स्थापना, बहुविद्याशाखीय शिक्षा, तकनिकी का ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा में उपयोग जैसे कई मुद्दों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि इस धारा का उद्देश्य प्रत्येक भागकारी को नई निर्माणात्मक बनाने में मदद करना है। देसाई कोली (२०२२) ने नई शैक्षिक नीति से गरीब और श्रीमंत वर्ग के बीच अंतर अधिक बढ़ जाएगा, इस नीति ने शिक्षा संस्थानों के सामने कई चुनौतियों को उत्पन्न किया है। वे यह भी कहते हैं कि इस नीति का शिक्षा क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव होगा और यह विश्व भर में महत्वपूर्ण है। जैन इ. (२०२२) ने इस नीति के विशिष्टता को बताते हुए कहा कि उच्च शिक्षा में छात्रों की नोंदणी और गुणवत्ता में सुधार के लिए यह नीति उपयुक्त हो सकती है। हालांकि, वे यह भी कहते हैं कि इसके बारे में और अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है, खासकर अवलोकन की बात करते समय। जैन पी. (२०२२) ने इस नीति का परीक्षण करते हुए इसके वर्तमान परिस्थितियों से संबंध बनाने और भविष्य में लागू करने के उपाय दिए हैं। इस शैक्षिक नीति को केवल लागू करने के रूप में नहीं देखा जा सकता है, बल्कि इसका प्रभाव राज्यों के साथ संवाद करके प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। सिंग बघेल (२०२०) ने प्राथमिक जानकारी के आधार पर बताया है कि इस नीति का उच्च शिक्षा क्षेत्र पर क्या प्रभाव हो सकता है। उनके अनुसार, इस धारा से छात्रों के सार्वजनिक विकास और सक्रियता को बढ़ावा मिलेगा। उच्च शिक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक और विशेष संस्थानों के लिए इस नई नीति का प्रभाव और इसका वैश्विक महत्व को ध्यान में रखकर चलन होगा ऐसा कहा है। इस अध्ययन में, निर्मल (२०२०) ने यह दर्शाया है कि उच्च शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक और विशेष संस्थानों द्वारा इस नए शैक्षिक धारा के प्रभाव को समझने और इसके वैश्विक महत्व को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी दिखाया है कि शिक्षकों को मूल उद्योगी शिक्षण पद्धतियों का अभ्यास करना चाहिए, स्थानीय परिसर के अनुसार व्यवसाय और उद्योग की शिक्षा देने के लिए कौशलों पर ध्यान देना चाहिए, और विद्यापीठों की स्थापना करनी चाहिए ताकि उन्हें शिक्षा और प्रबंधन की सार्वजनिक और विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने का समर्थन किया जा सके। यहां तक कि वे सुझाव देते हैं कि शिक्षा और प्रबंधन के क्षेत्र में इसके प्रत्युपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

इस अध्ययन का पुनरावलोकन करते समय, यह प्रतित्व किया जा सकता है कि सभी अभ्यासकों ने इस नई नीति के विशिष्टता, शिक्षा–अध्यापन पद्धतियाँ, संघटन और चुनौतियाँ, बलस्थान और कमकुवत स्थान, और शिक्षा क्षेत्र में प्रभाव के बारे में अध्ययन किया है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्रों ने स्थायी विकास के १७ लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से प्राथमिकता दी है, इसमें से चौथा लक्ष्य "गुणवत्ता शिक्षा" है, और इसके तहत उच्च शिक्षा और उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई कदम उठाए जाने चाहिए। इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि विद्यापीठों और उच्च शिक्षा संस्थानों में इस नई धारा का प्रावधान करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है।

अध्ययन समस्या

1. भारत सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कारण क्या स्थायी विकास का चौथा उद्देश्य "गुणवत्ता शिक्षा" साध्य होगा?
2. स्थायी विकास के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा के प्रत्याशित घटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल हैं?
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्थायी विकास के 'गुणवत्ता शिक्षा' उद्देश्य के साथ–संगत है?

तथ्य संकलन प्रविधी

इस अध्ययन के लिए प्राथमिक और द्वितीय स्रोतों का आधार लिया गया है और इसके लिए अनुभवजन्य अनुसंधान में यह स्वतंत्र प्रश्नावली के आधार पर संग्रहित किया गया है। इसके लिए पश्चिम महाराष्ट्र के महाविद्यालय शिक्षकों को निदर्श के रूप मे लिया गया है। प्रमुख १०० शिक्षकों को शोध अध्ययन विषय मे उद्देश्यात्मक निदर्श के रूप शामिल किया गया है। भारत देश स्थायी विकास की दिशा में मार्गदर्शन करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कौनसे घटक चाहिए ये यह अध्ययन बताता है। यह घटक शिक्षा नीति में शामिल किये गये है या नाही इसका पता करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की गई है। इसके लिए ५ पॉइंट लिकर्ट स्केल का आधार रखा गया है। लिकर्ट स्केल पद्धति को वैश्विक मान्यता मिली है और दृष्टिकोणों का मूल्यांकन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भावनाओंको व्यक्त करने के लिए इस पद्धति में बिल्कूल सहमत, सहमत, तटस्थ, असहमत, और बिल्कूल असहमत के ५ स्केल का उपयोग करके तथ्योका एकत्रिकरण किया गया है। द्वितीय स्रोतों के लिए किताबें, पत्रिकाएँ, ई–स्रोतों, समाचार पत्रिकाएँ आदि का आधार लिया गया है।

अध्ययन की सीमा

1. वर्तमान अनुसंधान में केवल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० और उच्च शिक्षा को सीमित किया गया है।
2. इस अध्ययन में स्थायी विकास के १७ उद्देश्यों में से केवल चौथे उद्देश्य "गुणवत्ता शिक्षा" परही ध्यान केंद्रित किया गया है।

तथ्य विश्लेषण और वर्गीकरण

इस सर्वेक्षण के लिए चुने गए महाविद्यालयों के शिक्षकों का लिंग और आयु के आधार पर वर्गीकरण निम्नलिखित है:

तालिका 1: चयनित महाविद्यालयों के शिक्षकों का लिंग और आयु के आधार पर वर्गीकरण

अ. क्र.	विवरण	कुल संख्या			कुल
	आयुवर्ग	२५–३५	३६–४५	४५ +	
१	महिला	८	२३	९	४० (४०%)
२	पुरुष	१२	२८	२०	६० (६०%)
कुल		२० (२०%)	५१ (५१%)	२९ (२९%)	१००

(**स्रोत:** प्राथमिक तथ्य संकलन और विश्लेषण)

ऊपर दिए गए तालिका क्रमांक १ में दिखाया गया है कि कुल चयनित शिक्षकों में महिला शिक्षकों की संख्या ४० है, जबकि पुरुष शिक्षकों की संख्या ६० है। आयु के आधार पर, आयु समूह २५ से ३५ वर्ष के बीच ८ महिला और १२ पुरुष शिक्षक हैं, ३६ से

४५ वर्ष के आयु समूह में २३ महिला और २८ पुरुष शिक्षक हैं, और ४५ वर्ष से अधिक आयु वाले महिला शिक्षक ६ हैं, जबकि पुरुष शिक्षक २० हैं। इस अध्ययन में महिला शिक्षकों की कुल संख्या ४० है, जबकि पुरुष शिक्षकों की कुल संख्या ६० है। इसका मतलब है कि वर्गवारी आधारित आयु गटों में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से अधिक है।

तालिका 2: राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० और स्थायी विकास के उद्देश्य के संदर्भ में दृष्टिकोण

अनुक्रमांक	नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिणामस्वरूप ...	बिल्कूल सहमत	सहमत	तटस्थ	असहमत	बिल्कूल असहमत
१	भारतीय शिक्षा पद्धति विद्यार्थीकेंद्रित होगी।	१५	६५	२०	--	--
२	एकेडेमिक बैंक क्रेडिट पद्धति छात्रों के लिए उपयुक्त होगी।	२४	६६	१०	--	--
३	नैक मानांकन प्रणाली में बदलाव होगा।	३२	५६	८	४	--
४	उद्योग क्षेत्र की शिक्षा में सहभागिता बढ़ेगी।	२	४०	३२	१५	११
५	आने वाले सभी बदलाव शिक्षकों और शिक्षा संस्थानों द्वारा स्वीकार किए जाएंगे।	२१	३६	२३	२०	--
६	NEP के प्रभावी अमलबजावणी के लिए शिक्षक खुद से खुद को बदलेंगे।	२५	६६	९	--	--
७	स्वायत्तता के कारण महाविद्यालयों को उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी।	१४	५४	२५	७	--
८	तकनीकी और व्यावसायिक कौशलों की विद्यार्थी संख्या में वृद्धि होगी।	३५	६५	७	३	--
९	मल्टिपल एंट्री और मल्टिपल एक्जिट के लाभ से छात्रों को फायदा होगा।	१९	४८	१५	१४	४
१०	छात्रों को मातृभाषा और बहुविद्याशाखीय शिक्षा मिलेगी।	२०	५२	१२	१६	--
११	आभासी पद्धति की शिक्षा को बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा।	३२	५६	१२	--	--
१२	तकनीक और कौशल विकास से रोजगार क्षमता बढ़ेगी।	२५	५७	१२	६	--
१३	दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में उपयुक्त कौशल छात्रों को मिलेगी।	१५	४०	२५	१०	१०
१४	निरंतर नवाचार की गई अनुसंधान क्षमता छात्रों में विकसित होगी।	--	५५	३३	१०	१२
१५	छात्रों के स्थायिता में रचनात्मकता का निर्माण होगा।	--	५३	३०	१४	३
१६	पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा का समावेश होगा।	१४	७१	१५	--	--
१७	पर्यावरण शिक्षा सक्ति के साथ छात्रों में जागरूकता को बढ़ावा देगी।	..	८७	९	४	..
१८	विश्व की प्राकृतिक संपत्ति की जानकारी छात्रों को मिलेगी।	१२	६५	२०	३	--
१९	स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, और न्याय जैसी लोकशाही मूल्यें छात्रों में बढ़ेंगी।	..	५४	३६	१०	..
२०	भाषा, विज्ञान, नागरिकशास्त्र, और भूगोल को स्थायी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी।	३०	५२	१०	८	--
२१	नागरिकों के अधिकार, कर्तव्यों, और जिम्मेदारियों की समझ छात्रों को मिलेगी।	२०	५०	३०	--	--
२२	वैश्विक समानता और बंधुता का निर्माण होने में मदद होगी।	२५	३५	२०	२०	--
२३	राष्ट्रीय एकात्मता और आंतरराष्ट्रीय सामंजस्य के विकास में मदद होगी।	१६	५३	२२	९	--
२४	2035 तक GER दर 50% तक वृद्धि होगी।	--	४४	२२	३४	--
२५	सरकार GDP का ६% खर्च उच्च शिक्षा पर करेगी[८]	--	--	२३	५६	२१

(**स्रोत:** प्राथमिक तथ्य संकलन और विश्लेषण)

तालिका क्रमांक २ से पता चलता है कि स्थायी विकास के चौथे उद्देश्य में जो गुणवत्ता शिक्षा शामिल है, उसमें अपेक्षित बातों की पूर्ति भारत सरकार द्वारा आगामी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से निश्चित रूप से होगी, ऐसा इस अध्ययन का निष्कर्ष सूचित करता है। इस नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा अधिक विद्यार्थियों केंद्रित होगी, इसे ८०% लोग मानते हैं। ८८% लोग यह बताते हैं कि अकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट छात्रों के लिए उपयुक्त होगा, और नैक मूल्यांकन पद्धति और तंत्र को भी कई बदलाव करने की आवश्यकता होगी। इस शिक्षा नीति को सभी शिक्षक और शिक्षा संस्थान स्वीकार करेंगे, इसे ५७% लोगों ने मान्यता दी है, और इस नीति की प्रभावी अमलबजावणी के लिए शिक्षक खुद को बदलने के लिए तैयार होंगे, इसे ६१% लोग मानते हैं।

नई शिक्षा नीति में महाविद्यालयों की संलग्नता खत्म होगी और महाविद्यालय स्वायत्तता को स्वीकार करेंगे। इस स्वायत्तता को स्वीकार करने के कारण उच्च शिक्षा के दर्जे में वृद्धि होगी, इसे ६८% लोगों ने माना है। २०३० तक तकनिक और व्यावसायिक कौशल वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि होगी, इसे ६०% लोगों ने कहा है। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एक्जिट (६७%), मातृभाषा में और बहुविद्याशाखीय शिक्षा (७२%), आभासी शिक्षा को बढ़ावा (८८%), तकनिक और कौशल विकास के माध्यम से रोजगार क्षमता में वृद्धि (८२%) ये सब दिखाई देता है की लोंग शिक्षा नीति पर अनुकूल है।

इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से छात्रों में निरंतर नए ज्ञान खोजने की प्रवृत्ति मजबूत होगी और उनमें सृजनात्मकता का निर्माण होगा, इसे ५५% लोग सहमत हैं। पाठ्यक्रम में व्यावसायिकता का समावेश करना अब आवश्यकता बन चुका है और इसके बारे में ८५% लोग आशावादी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राकृतिक संपदा की जानकारी छात्रों को सभी स्तरों पर उपलब्ध कराई जाएगी और उसमें भारतीय शिक्षा संस्थानों की प्रमुख भूमिका रहेगी ऐसी ७७% लोगो की राय हैं।

शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, और न्याय की लोकशाही मूल्यों का छात्रों में समर्थन बढ़ेगा, इसे ५४% लोग बताते हैं। भाषा, विज्ञान, नागरिकशास्त्र, और भूगोल को स्थायी विकास में महत्वपूर्ण माना जाएगा, इसे ८२% लोग समर्थन देते हैं, जबकि नागरिकों के अधिकार, कर्तव्यों, और जिम्मेदारियों की जागरूकता छात्रों को होगी (७०%), और वैश्विक समानता और बंधुता का निर्माण शिक्षा के माध्यम से होगा (५०%) इस पर लोंग अनुकूल राय देते हैं। राष्ट्रीय एकता और अंतरराष्ट्रीय सामंजस्य के विकास को शिक्षा के माध्यम से बढ़ावा मिलेगा, इसे ६६% लोगों ने सूचित किया है। और इसलिए नई शिक्षा नीति भारतीय

शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, इसे ७७% लोगों ने माना है।

इस प्रश्नावली में कुल २५ प्रश्नों में से केवल एक ही प्रश्न के साथ उत्तरकर्ता सहमत नहीं होते। यह आखिरी प्रश्न था – क्या सरकार GDP का ६% खर्च उच्च शिक्षा पर करेगी? इस पर ७७% उत्तरकर्ता असहमत हैं, जबकि २१% बिल्कूल असहमत हैं और ५६% असहमत हैं। फिर भी, ऊपर २३% लोग तटस्थ रहे हैं।

निष्कर्ष

एकवीसवीं सदी ज्ञान और तकनिकी का युग है, जो ज्ञान को शक्ति, ऊर्जा और संपत्ति माना जाता है। इस सदी में ज्ञान ही शक्ति, ऊर्जा और संपत्ति होगी। इसलिए ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस शताब्दी में नई शिक्षा नीति २०२० की घोषणा करके भारत सरकार ने सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षा की दिशा में योगदान किया है। हालांकि इस दिशा में भारत ने काफी देर की है, लेकिन इसे साकार करने के लिए अब बड़ा निवेश करने की आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि उच्च शिक्षा को प्रमोट करने के लिए भारत ने जीडीपी के ६% का खर्च करने की तैयारी करनी चाहिए, जिससे हमारे देश को विश्व गुरु बनाने का सुनहरा अवसर मिले। शिक्षा प्रक्रिया और शिक्षा नीति इस बारे में महत्वपूर्ण साधन हो सकते हैं, लेकिन इसे प्रत्यक्ष खर्च के साथ ही संभव बनाना होगा। दूसरा, उच्च शिक्षा में छात्रों के प्रमाण को २६% से ५०% तक बढ़ाने के लिए हमें महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की संख्या को दोगुना करने की आवश्यकता होगी। वर्तमान में भारत में १,११३ विश्वविद्यालय, ४३,७६६ महाविद्यालय और ११,२६६ स्वतंत्र संस्थान हैं, और इस संख्या को दोगुना करने की आवश्यकता है। इसके लिए बड़ी मात्रा में निवेश की आवश्यकता होगी। स्वतंत्रता से जीडीपी के ६% का शिक्षा पर खर्च का प्रावधान तो हैं लेकिन आज तक उसकी ओर ध्यान दिलाने का प्रयास नही किया गया हैं।

स्वीकृति (Acknowledgement)

लेखक इस शोध के लिए डेटा प्रदान करने में उनके बहुमूल्य समर्थन के लिए पुणे जिले के विभिन्न कॉलेजों के शिक्षण कर्मचारियों और छात्रों को ईमानदारी से धन्यवाद देते हैं। इस अध्ययन के सफल समापन के लिए उनका सहयोग और योगदान आवश्यक था।

फंडिंग विवरण (Funding Details)

यह शोध बिना किसी बाहरी फंडिंग के आयोजित किया गया था।

लेखक का योगदान (Author Contribution)

लेखक 1 ने अध्ययन की संकल्पना की है और विश्लेषण किया है। लेखक 2 ने कार्यप्रणाली और डेटा संग्रह में योगदान दिया। लेखक 3 ने पांडुलिपि लेखन और समीक्षा में सहायता की। अंतिम पांडुलिपि को सभी लेखकों ने पढ़ा है और मंजूरी दी है।

हितो का टकराव (Conflict of Interest)

लेखक इस अध्ययन से संबंधित हितों के टकराव की घोषणा नहीं करते हैं।

नैतिक कथन (Ethical Statement)

यह शोध नैतिक मानकों का अनुपालन करता है और इसमें नैतिक अनुमोदन की आवश्यकता वाले किसी भी मानव या पशु प्रतिभागी को शामिल नहीं किया गया है।

संदर्भ

1. २१ व्या शतकासाठी शिक्षण, प्रथम वर्ष कला सत्र २, मुंबई विद्यापीठ, फेब्रुवारी २०२१ पृष्ठ ३५–४०
2. Abhay Kumar (2022) Importance of National Education Policy 2020 in Imparting Education, Journal of Positive School Psychology, Vol. 6 (2), pp. 6557–6561
3. Chavan J. S. (2023) Rashtria Shaikshanik Dhoran 2020: samasya ani Avhane, International Journal of Advance and Applied Research, Vol. 4(14), March-April 2023, www.ijaar.co.in pp.56-59
4. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjW9fqQhbSBAxVNxDgGHQbVCms4FBAWegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ftestbook.com%2Fugc-net-paper-1%2Fnep-2020&usg=AOvVaw1sJQfflzxTiZASxFR5p nt8&opi=89978449 Retrieved on 21/09/2023
5. Jain Priyanka (2022), Implementation of New Education Policy 2020 in Higher Education System of Indian Universities: A State wise Review, International Journal for Research Trends and Innovation, Vol. 7(5), pp. 236-245
6. N. Jain, R. Jain, P. Saini, (2022), Analysis of NEP 2020 in the Light of NAAC Accreditation: An Analytical Study of Academicians Opinion December, Vol. 10 (XII), pp. 799-802
7. Nirmal Balasaheb (2022) Navin Shaikshanik Dhoran 2020 Sandhi ani Avhane, Review of Research, Vol. 11 (10), July, pp.34-39
8. P. S. Desai & V. M. Koli (2022) Mulodyogi Shikshan Vishayak Tattvancha Rashtriy Shaikshanik Dhoran 2020 varil Prabhav, Navjyot, Vol. XII (I), pp. 454-456 www.navjyot.net
9. Parul Nagpal (2023) Implementing the National Education Policy 2020: Challenges and Solutions in School Education in India, International Journal of Creative Research Thoughts, Vol.11 (1), January, pp. e828-e831
10. Significant increase in number of universities/IITs/IIMs in last 9 years: MoE | The Financial Express Retrieved on 18/09/2023
11. Sustainable Development Through EducationSustainable Development Multidisciplinary Education, शिक्षणातून शाश्वत विकास – sustainable development through education - Maharashtra Times Retrieved on 20/09/2023
12. U. S. Singh & S. S. Baghel (2020) Insights and Perspectives of NEP in Transforming Higher Education in India, International Research Journal of Humanities and Interdisciplinary Studies, Vol. 1 (2), pp. 30-41
13. नवे शैक्षणिक धोरण आणि पाच आव्हाने | ORF (orfonline.org) Retrieved on 20/09/2023
14. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंमलबजावणी आव्हाने – डॉ. प्रतिक मुणगेकर (aimsolute.com) Retrieved on 20/09/2023
15. शाश्वत विकास ध्येये (Sustainable Development Goals) – मराठी विश्वकोश (marathivishwakosh.org) Retrieved on 20/09/2023